

# ग्रामीण समाज पर सोशल मीडिया का प्रभाव: सामाजिक परिवर्तन, डिजिटल विभाजन एवं ग्रामीण विकास का समाजशास्त्रीय अध्ययन

**Mr. Santosh Kumar**

Assistant Professor, Sociology, Veer Bahadur Singh Government Degree College  
Caimpianganj Gorakhpur

## सारांश

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक मीडिया धीरे-धीरे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है। मोबाइल फोन तथा इंटरनेट आधारित मंचों के विस्तार ने संचार, सूचना के आदान-प्रदान, शिक्षा, विपणन, जनभागीदारी तथा सरकारी एवं जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी तक पहुँच के अवसरों में वृद्धि की है। मोबाइल फोन और इंटरनेट आधारित मंचों ने ग्रामीण निवासियों को स्थानीय संबंधों के साथ-साथ व्यापक सामाजिक एवं सूचना-नेटवर्क से जुड़ने के अवसर प्रदान किए हैं। ग्रामीण नागरिक तथा किसान, विद्यार्थी महिलाएँ इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तथा अपने जीवन स्तर को ऊँचा कर रहे हैं। परिवर्तन के दृष्टि से देखा जाय तो इस परिवर्तन पीछे कई कारकों में से एक सामाजिक मीडिया भी है। सामाजिक मीडिया ने ग्रामीण समाज को गहराई से प्रभावित किया है लेकिन यह प्रभाव व्यापक नहीं है और न ही समान रूप से वितरित है। इंटरनेट की उपलब्धता, नेटवर्क की गुणवत्ता, उपकरणों की कीमत, डेटा की वहनीयता, डिजिटल कौशल, शिक्षा, आय, लिंग तथा सामाजिक स्थिति डिजिटल सहभागिता की प्रकृति को प्रभावित करते हैं। भ्रामक सूचना, निजता का उल्लंघन, साइबर धोखाधड़ी, ऑनलाइन उत्पीड़न तथा डिजिटल निर्भरता जैसी चुनौतियाँ भी ग्रामीण समाज के सामने उपस्थित हैं। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य ग्रामीण समाज में सोशल मीडिया की भूमिका का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है। अध्ययन द्वितीयक स्रोतों, सहकर्मी-समीक्षित साहित्य, संस्थागत प्रकाशनों तथा सरकारी सूचनाओं पर आधारित वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पुनरावलोकन है। अध्ययन में सामाजिक मीडिया को केवल तकनीकी मंच के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक नेटवर्क, सामाजिक पूँजी और ग्रामीण विकास से जुड़ी व्यवस्था के रूप में समझा गया है। विश्लेषण में डिजिटल पहुँच, डिजिटल कौशल, उपयोग, परिणाम और जोखिम को प्रमुख आयाम माना गया है। उपलब्ध विभिन्न शोध साहित्य से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण समाज में सामाजिक मीडिया पारंपरिक सामाजिक संस्थाओं का पूर्ण विकल्प नहीं है, बल्कि परिवार, जाति, समुदाय, स्वयं सहायता समूह, बाजार, विद्यालय तथा स्थानीय शासन के साथ अंतःक्रिया करते हुए सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। अध्ययन यह भी रेखांकित करता है कि डिजिटल समावेशन के लिए केवल इंटरनेट संपर्क पर्याप्त नहीं है; सार्थक डिजिटल सहभागिता हेतु उपकरणों पर स्वतंत्र नियंत्रण, स्थानीय भाषा में सामग्री, डिजिटल एवं मीडिया साक्षरता, साइबर सुरक्षा तथा उत्पादक उपयोग के अवसर आवश्यक हैं।

**मुख्य शब्द:** ग्रामीण समाज, सोशल मीडिया, डिजिटल विभाजन, डिजिटल समावेशन, ग्रामीण विकास, डिजिटल साक्षरता, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक पूंजी।

## प्रस्तावना

ग्रामीण समाज का सामाजिक जीवन परंपरागत रूप से आमने-सामने की अंतःक्रिया, नातेदारी, जाति, वर्ग, समुदाय, स्थानीय संस्थाओं, कृषि और प्रथागत व्यवहारों पर आधारित रहा है। मोबाइल इंटरनेट के विस्तार ने इन संबंधों में एक नया डिजिटल आयाम जोड़ा है। सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से ग्रामीण निवासी परिवार एवं मित्रों से संपर्क बनाए रखने के साथ-साथ रुचि और हित आधारित समूहों में भाग ले सकते हैं, अपने अनुभव, ज्ञान व सूचना साझा कर सकते हैं, अपने उत्पादों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और व्यापक सार्वजनिक सामाजिक विमर्श से जुड़ सकते हैं। इस प्रकार सामाजिक मीडिया ने भौगोलिक दूरी को कम करने और सूचना के प्रसार को गति देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। ग्रामीण समाज में सोशल मीडिया की भूमिका को समझना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि डिजिटल माध्यम अब केवल मनोरंजन या व्यक्तिगत संवाद तक सीमित नहीं रहे। कृषि, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक बदलाव, बाजार, सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता, स्थानीय प्रशासन तथा सामुदायिक गतिविधियों में भी इनका उपयोग बढ़ा है। किसान कृषि संबंधी अनुभव साझा कर सकते हैं, विद्यार्थी शैक्षणिक वीडियो और परीक्षा-संबंधी सामग्री प्राप्त कर सकते हैं, ग्रामीण उद्यमी ग्राहकों तक पहुँच बनाने का प्रयास कर सकते हैं और स्वयं सहायता समूह अपने उत्पादों को व्यापक बाजार तक ले जाने के लिए डिजिटल मंचों का उपयोग कर सकते हैं। फिर भी सोशल मीडिया को ग्रामीण विकास का स्वतः प्रभावी साधन मानना उचित नहीं है। डिजिटल संसाधनों तक पहुँच सामाजिक-आर्थिक स्थिति के अनुसार अलग-अलग होती है। एक परिवार में स्मार्टफोन की उपलब्धता होने पर भी सभी सदस्यों को उस उपकरण पर समान नियंत्रण प्राप्त हो, यह आवश्यक नहीं है। विशेष रूप से महिलाओं के संदर्भ में उपकरण के स्वामित्व, निजी उपयोग की स्वतंत्रता और डिजिटल कौशल का प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार कमजोर नेटवर्क, महंगा डेटा, कम डिजिटल साक्षरता तथा भ्रामक सूचना डिजिटल अवसरों को सीमित कर सकती है। इसलिए ग्रामीण समाज पर सोशल मीडिया के प्रभाव को अवसर और चुनौती दोनों के संदर्भ में समझना आवश्यक है।

## अध्ययन के उद्देश्य

1. ग्रामीण समाज में सोशल मीडिया द्वारा सामाजिक संबंधों और संचार में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना।
2. कृषि, शिक्षा, रोजगार, बाजार, उद्यमिता तथा नागरिक सहभागिता में सोशल मीडिया की भूमिका का विश्लेषण करना।
3. डिजिटल विभाजन के आधारभूत, आर्थिक, शैक्षणिक और लैंगिक आयामों की पहचान करना।
4. भ्रामक सूचना, निजता, साइबर सुरक्षा तथा ऑनलाइन उत्पीड़न जैसी चुनौतियों का विश्लेषण करना।
5. ग्रामीण समुदायों में समावेशी, सुरक्षित और उत्पादक डिजिटल सहभागिता के लिए आवश्यक उपायों को रेखांकित करना।

## शोध प्रश्न

1. सोशल मीडिया ग्रामीण समुदायों में संचार और सामाजिक अंतःक्रिया को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है?
2. ग्रामीण विकास के किन क्षेत्रों में सोशल मीडिया अवसर उत्पन्न करता है?

3. ग्रामीण समाज में डिजिटल लाभों तक पहुँच किन सामाजिक एवं आर्थिक कारकों से प्रभावित होती है?
4. डिजिटल विभाजन, भ्रामक सूचना और साइबर जोखिम ग्रामीण डिजिटल सहभागिता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं?
5. समावेशी एवं उत्तरदायी डिजिटल सहभागिता के लिए कौन-से उपाय आवश्यक हैं?

### शोध-प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन द्वितीयक स्रोतों पर आधारित वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पुनरावलोकन पद्धति का उपयोग करता है। मूल सामग्री में ग्रामीण डिजिटल असमानता, सोशल मीडिया, सामुदायिक मीडिया, डिजिटल साक्षरता और ग्रामीण विकास से संबंधित सहकर्मी-समीक्षित शोध-पत्रों तथा संस्थागत प्रकाशनों का अध्ययन किया गया है। इसके साथ भारत सरकार के स्रोतों और प्रेस सूचना ब्यूरो से उपलब्ध सामग्री को भी शामिल किया गया है। अध्ययन का उद्देश्य उपलब्ध साहित्य और अनुभवजन्य संकेतकों को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से व्यवस्थित करके ग्रामीण समाज पर सोशल मीडिया के प्रभाव की समग्र समझ विकसित करना है। स्रोतों को चार व्यापक श्रेणियों में देखा गया है—शैक्षणिक शोध, सरकारी एवं संस्थागत रिपोर्ट, राष्ट्रीय डिजिटल उपयोग संबंधी आँकड़े और ग्रामीण डिजिटल समावेशन से संबंधित अनुभवजन्य अध्ययन। विश्लेषण के लिए पाँच प्रमुख आयाम निर्धारित किए गए हैं: डिजिटल पहुँच, डिजिटल कौशल, उपयोग का उद्देश्य, उपयोग के परिणाम और डिजिटल जोखिम। सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में लिंग, आयु, शिक्षा, आय, व्यवसाय और सामाजिक स्थिति जैसे कारकों पर ध्यान दिया गया है।

अध्ययन की एक महत्वपूर्ण सीमा यह है कि इसमें स्वयं एकत्रित प्राथमिक क्षेत्रीय आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए शोध-पत्र में दिए गए निष्कर्षों को पूरे ग्रामीण भारत पर समान रूप से लागू करने के बजाय उपलब्ध साहित्य और स्रोतों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। भविष्य में प्रश्नावली, अर्द्ध-संरचित साक्षात्कार और क्षेत्रीय सर्वेक्षण के माध्यम से इन निष्कर्षों का प्राथमिक स्तर पर परीक्षण किया जा सकता है।

### साहित्य समीक्षा

ग्रामीण समाज में डिजिटल परिवर्तन पर उपलब्ध साहित्य यह संकेत देता है कि डिजिटल विभाजन केवल इंटरनेट उपलब्धता का प्रश्न नहीं है। उपकरण, नेटवर्क, आर्थिक वहनीयता, डिजिटल कौशल, भाषा, सामाजिक स्वायत्तता और उपयोग की गुणवत्ता इसके महत्वपूर्ण घटक हैं। Laskar (2023) ने भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के डिजिटल विभाजन की तुलना करते हुए इंटरनेट उपलब्धता और उससे प्राप्त वास्तविक सामाजिक लाभों के बीच अंतर की ओर संकेत किया है। इससे स्पष्ट होता है कि डिजिटल पहुँच की गणना को सामाजिक परिणामों से अलग करके नहीं देखा जा सकता।

ग्रामीण युवाओं से संबंधित Pandey (2026) के अध्ययन में सोशल मीडिया के सामाजिक व्यवहार, शैक्षणिक आकांक्षाओं, ऑनलाइन अधिगम तथा रोजगार एवं प्रवासन संबंधी जागरूकता के संदर्भ पर ध्यान दिया गया है। यह अध्ययन इस आवश्यकता की ओर संकेत करता है कि ग्रामीण युवाओं के डिजिटल उपयोग को केवल उपयोगकर्ता संख्या से नहीं, बल्कि उपयोग के उद्देश्य और परिणामों से समझा जाए। Pradhiba (2026) ने ग्रामीण दक्षिण भारत में डिजिटल विभाजन को बहुआयामी समस्या के रूप में देखने पर बल दिया है। इन अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि डिजिटल सहभागिता सामाजिक पृष्ठभूमि से स्वतंत्र प्रक्रिया नहीं है।

Rampal (2019) ने ग्रामीण समाज के विकास में सोशल मीडिया की भूमिका पर उपलब्ध साहित्य की समीक्षा करते हुए संचार, सूचना प्रसार और विकासात्मक उपयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। इस साहित्य में सोशल मीडिया की उपयोगिता के अनेक उदाहरण मिलते हैं, लेकिन ग्रामीण परिवारों के भीतर उपकरण के स्वामित्व, नियंत्रण और वास्तविक उपयोग की सूक्ष्मता पर अधिक क्षेत्रीय शोध की आवश्यकता बनी रहती है। विशेष रूप से महिलाओं, वृद्धों, निम्न-आय परिवारों और सामाजिक रूप से वंचित समूहों के अनुभवों को अलग-अलग समझना आवश्यक है।

डिजिटल साक्षरता संबंधी साहित्य यह स्पष्ट करता है कि इंटरनेट तक पहुँच मात्र से सार्थक डिजिटल समावेशन सुनिश्चित नहीं होता। डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण उपयोगकर्ताओं को सूचना खोजने, उसकी विश्वसनीयता जाँचने, डिजिटल सामग्री तैयार करने तथा सुरक्षित रूप से ऑनलाइन गतिविधियाँ करने में सक्षम बना सकता है। इसलिए डिजिटल समावेशन को आधारभूत संरचना और कौशल दोनों से जोड़कर देखना आवश्यक है।

IAMAI-Kantar के Internet in India 2024 अध्ययन से ग्रामीण क्षेत्रों में साझा उपकरणों के उपयोग का मुद्दा सामने आता है। मूल सामग्री में उद्धृत रिपोर्ट के अनुसार 2024 में ग्रामीण क्षेत्रों में किसी अन्य व्यक्ति के मोबाइल से इंटरनेट उपयोग करने वाले साझा-उपकरण उपयोगकर्ताओं का अनुपात 24 प्रतिशत बताया गया है। यह तथ्य दर्शाता है कि उपकरण की उपलब्धता और उपकरण पर व्यक्तिगत नियंत्रण दो अलग-अलग प्रश्न हैं। इस साहित्य समीक्षा से मुख्य शोध-अंतराल यह उभरता है कि ग्रामीण सोशल मीडिया अध्ययन में पहुँच, नियंत्रण, कौशल, उपयोग के उद्देश्य और वास्तविक परिणामों को एक संयुक्त विश्लेषणात्मक ढाँचे में अधिक व्यवस्थित रूप से देखना आवश्यक है।

### वैचारिक रूपरेखा

प्रस्तुत अध्ययन में सोशल मीडिया को डिजिटल तकनीक के साथ-साथ सामाजिक अंतःक्रिया के एक नए क्षेत्र के रूप में समझा गया है। इसके लिए डिजिटल विभाजन, सामाजिक नेटवर्क, सामाजिक पूँजी और डिजिटल समावेशन की अवधारणाओं को परस्पर संबद्ध माना गया है। ग्रामीण व्यक्ति अपने पारंपरिक सामाजिक संबंधों को बनाए रखते हुए डिजिटल माध्यम से नए सूचना-नेटवर्क और संपर्क स्थापित कर सकता है। इस प्रकार पारंपरिक सामाजिक पूँजी और डिजिटल सामाजिक पूँजी के बीच अंतःक्रिया की संभावना उत्पन्न होती है।

इस विश्लेषण में पाँच प्रमुख आयाम हैं। पहला, पहुँच—जिसमें मोबाइल फोन, इंटरनेट, नेटवर्क कवरेज और डेटा की वहनीयता शामिल है। दूसरा, कौशल—जिसमें सूचना खोजना, सूचना की विश्वसनीयता जाँचना, सामग्री बनाना और साइबर सुरक्षा का पालन करना शामिल है। तीसरा, उपयोग—जिसमें शिक्षा, कृषि, रोजगार, व्यवसाय, सामाजिक संपर्क और नागरिक सहभागिता जैसे उद्देश्य आते हैं। चौथा, परिणाम—जिसमें ज्ञान, आर्थिक अवसर, सामाजिक नेटवर्क, सेवाओं तक पहुँच और नागरिक सहभागिता में परिवर्तन शामिल हैं। पाँचवाँ, जोखिम—जिसमें भ्रामक सूचना, निजता का उल्लंघन, साइबर धोखाधड़ी, ऑनलाइन उत्पीड़न और सामाजिक संघर्ष सम्मिलित हैं।

यह रूपरेखा बताती है कि समान इंटरनेट पहुँच वाले दो व्यक्तियों के सामाजिक परिणाम समान होना आवश्यक नहीं है। शिक्षा, आय, लिंग, आयु, सामाजिक स्थिति और उपकरण पर नियंत्रण उपयोग की प्रकृति को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए डिजिटल समावेशन को केवल तकनीकी पहुँच के बजाय सामाजिक क्षमता और परिणामों के संदर्भ में देखना अधिक उपयुक्त है।

### सामाजिक संबंध और ग्रामीण सामाजिक संरचना

सोशल मीडिया ग्रामीण समाज में सामाजिक अंतःक्रिया का एक अतिरिक्त क्षेत्र निर्मित करता है। परिवार के सदस्य, प्रवासी श्रमिक, विद्यार्थी, किसान, उद्यमी और सामुदायिक कार्यकर्ता डिजिटल माध्यमों से निरंतर संपर्क बनाए रख सकते हैं। इससे भौगोलिक दूरी के बावजूद संबंधों की निरंतरता संभव होती है। स्थानीय आयोजनों, आपात स्थितियों और सामुदायिक पहलों में सूचना के तीव्र आदान-प्रदान से समन्वय की संभावना भी बढ़ती है। हालाँकि, डिजिटल संपर्क पारंपरिक सामाजिक संरचना को समाप्त नहीं करता। जाति, वर्ग, लिंग, आय, शिक्षा और सामाजिक स्थिति जैसी संरचनात्मक विशेषताएँ डिजिटल संसाधनों तक पहुँच और उनके उपयोग को प्रभावित करती हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास उपकरण या नेटवर्क की सुविधा नहीं है, तो वह डिजिटल नेटवर्क से अपेक्षाकृत बाहर रह सकता है। इसी प्रकार डिजिटल समूह भी कभी-कभी मौजूदा सामाजिक संबंधों और पहचान के आधार पर संगठित हो सकते हैं। इसलिए सोशल मीडिया को पारंपरिक ग्रामीण समाज के विकल्प के बजाय उसके साथ अंतःक्रिया करने वाली व्यवस्था के रूप में समझना आवश्यक है।

### कृषि, बाजार और ग्रामीण आजीविका

कृषि क्षेत्र में सोशल मीडिया आज किसानों के लिए नई नई कृषि तकनीक, मौसम, बाजार, फसल प्रबंधन और अनुभवों के आदान-प्रदान का एक महातपूर्ण माध्यम है। किसान समूहों के माध्यम से स्थानीय समस्याओं पर चर्चा, कृषि संबंधी सामग्री का प्रसार और उत्पादों के बाजार की जानकारी प्राप्त कर रहे व साझा कर रहे हैं। ग्रामीण उद्यमी भी सामाजिक मीडिया का उपयोग द्वारा अपने उत्पादों के प्रचार प्रसार, ग्राहकों से संपर्क और स्थानीय बाजार की सीमाओं से आगे पहुँच बनाने के लिए कर रहे हैं। इसके बावजूद केवल सूचना की उपलब्धता को सीधे आर्थिक लाभ का प्रमाण नहीं माना जा सकता। कृषि संबंधी डिजिटल सूचना की विश्वसनीयता, किसान की उसे समझने की क्षमता, स्थानीय परिस्थितियों से उसकी संगति और निर्णय लेने में उसके वास्तविक उपयोग को मापना आवश्यक है। यदि किसी किसान को बाजार मूल्य की सूचना मिलती है, तो यह भी देखना होगा कि क्या उसने उस सूचना के आधार पर विपणन निर्णय बदला और क्या उसके आर्थिक परिणाम में मापनीय परिवर्तन हुआ। इसलिए भविष्य के क्षेत्रीय अध्ययन में सूचना प्राप्ति, सूचना सत्यापन, निर्णय और आर्थिक परिणाम के बीच संबंध का परीक्षण किया जाना चाहिए।

### शिक्षा और युवा

ग्रामीण युवाओं के लिए सोशल मीडिया शैक्षणिक वीडियो, प्रतियोगी परीक्षाओं की सामग्री, कौशल विकास, रोजगार और व्यवसाय संबंधी सूचना आदि का महत्वपूर्ण स्रोत है। इससे जहाँ औपचारिक संस्थानों के बाहर उपलब्ध सीखने के अवसरों का विस्तार होता है वही युवाओं के सामाजिक नेटवर्क भी व्यापक होता है जिससे उन्हें नए शैक्षणिक और व्यावसायिक अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। परंतु यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि डिजिटल सामग्री की उपलब्धता और वास्तविक अधिगम में अंतर है। अध्ययन-अवधि, सामग्री की गुणवत्ता, सूचना की विश्वसनीयता, नियमित उपयोग और सीखने के परिणामों को अलग-अलग मापना आवश्यक है। मनोरंजन-प्रधान सामग्री, भ्रामक सूचना और ध्यान भटकने की संभावना भी मौजूद है। इसलिए सोशल मीडिया को शिक्षा का पूर्ण विकल्प न मानकर पूरक संसाधन के रूप में देखना

अधिक उपयुक्त है। डिजिटल और मीडिया साक्षरता युवाओं को विश्वसनीय और अविश्वसनीय सामग्री के बीच अंतर करने में सहायता कर सकती है।

### **ग्रामीण महिलाएँ और स्वयं सहायता समूह**

सोशल मीडिया ने ग्रामीण महिलाओं को बहुत घनिष्टता से प्रभावित किया है। ग्रामीण महिलाओं के लिए सोशल मीडिया आज सूचना, नेटवर्क निर्माण, उद्यमिता और स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों से जुड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। ग्रामीण समूह की महिलाएँ जो किसी प्रकार का व्यवसाय या गृहउद्योग संचालित करती हैं वे इसके द्वारा अपने उत्पादों का प्रचार कर सकती हैं, अन्य समूहों व्यवसायिक समूहों से संपर्क स्थापित कर सकती हैं तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं कार्यक्रमों एवं अवसरों की जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। इस प्रकार डिजिटल मंच वर्तमान में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक सहभागिता के लिए नए अवसर उपलब्ध कराने का एक नवीन साधन बन गया है। निश्चित तौर पर ग्रामीण महिलाओं के डिजिटली सशक्तिकरण का प्रमुख संकेतक है। लेकिन महिला डिजिटल सशक्तिकरण का आकलन केवल परिवार में स्मार्टफोन की उपलब्धता से नहीं किया जा सकता। यह देखना आवश्यक है कि उपकरण पर नियंत्रण किसका है, महिला उसे निजी रूप से कितना उपयोग कर सकती है, उसके पास डिजिटल कौशल कितना है और ऑनलाइन गतिविधियों के लिए उसे कितना सामाजिक समर्थन प्राप्त है। यदि उपकरण साझा है या उपयोग पर पारिवारिक नियंत्रण अधिक है, तो डिजिटल अवसर सीमित हो सकते हैं। इसलिए महिला डिजिटल समावेशन में उपकरण की स्वतंत्र पहुँच, कौशल प्रशिक्षण, सुरक्षित उपयोग और आर्थिक उपयोग के अवसरों को एक साथ देखना आवश्यक है।

### **नागरिक सहभागिता और स्थानीय शासन**

डिजिटल मंच जैसे सोशल मीडिया सरकारी योजनाओं कार्यक्रमों, सार्वजनिक घोषणाओं, स्थानीय समस्याओं और नागरिक सेवाओं से संबंधित जानकारी प्रसारित करने में सहायक हैं। इसके द्वारा नागरिक शिकायतों को साझा कर सकते हैं, स्थानीय समस्याओं पर चर्चा कर उसके समाधान की योजना बना सकते हैं, सामुदायिक कार्रवाई के लिए समन्वय बनाने में भी इनका उपयोग कर सकते हैं। डिजिटल माध्यमों की उपयोगिता बढ़ सकती है जब आधिकारिक सूचना स्थानीय भाषा में उपलब्ध हो। लेकिन इसके साथ सूचना की पुष्टि की आवश्यकता भी महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री हमेशा आधिकारिक या विश्वसनीय नहीं होती। इसलिए सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य, कानून और सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित सूचना को विश्वसनीय संस्थागत स्रोत से सत्यापित करना आवश्यक है। नागरिक सहभागिता की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि उपयोगकर्ता सूचना तक पहुँचने के साथ-साथ उसकी विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने में भी सक्षम हैं या नहीं।

### **सोशल मीडिया के सकारात्मक एवं नकारात्मक आयाम एवं जोखिम**

सोशल मीडिया ग्रामीण समाज में अवसरों के साथ अनेक जोखिम भी उत्पन्न करता है। इसलिए सोशल मीडिया के सामाजिक प्रभाव को सरल सकारात्मक-नकारात्मक द्विभाजन से समझना पर्याप्त नहीं है। सामाजिक संबंधों में यह तीव्र संचार और व्यापक नेटवर्क उपलब्ध कराता है, पर अफवाह और निजता संबंधी जोखिम भी पैदा कर सकता है। कृषि में पारस्परिक अधिगम और बाजार सूचना उपलब्ध हो सकती है, लेकिन अप्रमाणित सलाह भी फैल सकती है। शिक्षा में अध्ययन सामग्री और रोजगार सूचना मिल सकती है, किंतु ध्यान भटकने और भ्रामक सामग्री की समस्या रहती है। महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के लिए उद्यमिता और नेटवर्क निर्माण की संभावनाएँ बढ़ सकती हैं, लेकिन उपकरणों

तक असमान पहुँच और ऑनलाइन उत्पीड़न बाधा बन सकते हैं। शासन में योजनाओं की जानकारी और नागरिक सहभागिता संभव है, जबकि गलत सूचना और धोखाधड़ी जोखिम पैदा कर सकते हैं। स्थानीय व्यवसायों को उत्पाद प्रचार और ग्राहक पहुँच का लाभ मिल सकता है, लेकिन डिजिटल मंचों पर निर्भरता और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ सकती है।

इस तुलना से स्पष्ट होता है कि सोशल मीडिया का परिणाम उपयोगकर्ता, सामाजिक संदर्भ और संस्थागत वातावरण पर निर्भर करता है। इसलिए किसी एक क्षेत्र में दिखाई देने वाले लाभ को सभी ग्रामीण समुदायों के लिए समान प्रभाव नहीं माना जा सकता। उपलब्ध साहित्य और अनुभवजन्य संकेतकों को एक साथ देखने पर ग्रामीण समाज में सोशल मीडिया का प्रभाव बहुआयामी दिखाई देता है। यह सामाजिक पूँजी के विस्तार और सूचना तक पहुँच का माध्यम बन सकता है, लेकिन मौजूदा असमानताओं को डिजिटल क्षेत्र में पुनरुत्पादित भी कर सकता है। इसलिए प्रभाव का निर्धारण तकनीक अकेले नहीं करती; सामाजिक संरचना, संसाधनों तक पहुँच, डिजिटल क्षमता और संस्थागत संदर्भ मिलकर परिणामों को प्रभावित करते हैं।

कृषि में सूचना की उपलब्धता तभी उपयोगी है जब वह विश्वसनीय, समझने योग्य और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हो। शिक्षा में सामग्री की उपलब्धता तभी सार्थक है जब विद्यार्थी उसका नियमित और उद्देश्यपूर्ण उपयोग कर सके। महिलाओं के लिए डिजिटल अवसर तभी अधिक प्रभावी हो सकते हैं जब उपकरण और उपयोग पर वास्तविक स्वायत्तता उपलब्ध हो। इसी प्रकार नागरिक सहभागिता में सूचना की गति से अधिक उसकी विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है। इसलिए ग्रामीण डिजिटल परिवर्तन को पहुँच, क्षमता और परिणाम के तीन परस्पर जुड़े स्तरों पर समझना उपयोगी है। पहुँच में नेटवर्क और उपकरण आते हैं; क्षमता में डिजिटल कौशल, मीडिया साक्षरता और स्वतंत्र उपयोग शामिल हैं; परिणाम में शिक्षा, आजीविका, सामाजिक नेटवर्क और नागरिक सहभागिता जैसे वास्तविक परिवर्तन आते हैं। इस दृष्टिकोण से सोशल मीडिया को ग्रामीण विकास का स्वतः परिणाम देने वाला साधन न मानकर सामाजिक-सांस्कृतिक संसाधन के रूप में देखा जा सकता है।

### सैद्धांतिक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य

ग्रामीण समाज में सोशल मीडिया की भूमिका को समझने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक पूँजी और आधुनिकीकरण से संबंधित समाजशास्त्रीय अवधारणाएँ उपयोगी हैं। सामाजिक अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण से देखा जाए तो डिजिटल मंच ऐसे प्रतीकात्मक क्षेत्र हैं जहाँ व्यक्ति संदेश, चित्र, वीडियो और अन्य डिजिटल संकेतों के माध्यम से अर्थों का निर्माण और पुनर्निर्माण करते हैं। ग्रामीण व्यक्ति की सामाजिक पहचान अब केवल स्थानीय भौगोलिक संदर्भ से निर्धारित नहीं होती, बल्कि डिजिटल समूहों और व्यापक सामाजिक नेटवर्कों से जुड़कर उसका अनुभव विस्तृत हो सकता है।

सामाजिक पूँजी के संदर्भ में सोशल मीडिया पारिवारिक, सामुदायिक और व्यावसायिक संबंधों को बनाए रखने तथा नए संपर्कों के निर्माण में सहायता कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासन के कारण परिवार के सदस्य अलग-अलग स्थानों पर रहते हैं; डिजिटल माध्यम नियमित संपर्क बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं। इसी प्रकार किसान, विद्यार्थी, स्वयं सहायता समूह और छोटे उद्यमी समान रुचि वाले व्यक्तियों से जुड़कर सूचना और अनुभव साझा कर सकते हैं। लेकिन सामाजिक पूँजी का डिजिटल विस्तार तभी व्यापक होगा जब विभिन्न सामाजिक समूहों को डिजिटल संसाधनों तक समान अवसर प्राप्त हों।

आधुनिकीकरण के दृष्टिकोण से डिजिटल संचार ग्रामीण समाज में सूचना के प्रवाह और संस्थागत संपर्क के नए रूपों को जन्म दे सकता है। फिर भी डिजिटल परिवर्तन को पारंपरिक संस्थाओं के समाप्त होने की प्रक्रिया मानना उचित नहीं है।

ग्रामीण परिवार, जाति, समुदाय और स्थानीय संस्थाएँ डिजिटल माध्यमों के साथ अनुकूलन करती हैं। इसलिए सोशल मीडिया ग्रामीण आधुनिकीकरण की एक प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें पारंपरिक और आधुनिक संचार प्रणालियाँ साथ-साथ कार्य करती हैं।

### **परिवार, समुदाय और सामाजिक परिवर्तन**

सोशल मीडिया के विस्तार से ग्रामीण परिवारों के भीतर संचार की गति और स्वरूप में परिवर्तन दिखाई देता है। प्रवासी सदस्यों से संपर्क, पारिवारिक आयोजनों की सूचना, सामाजिक संबंधों का रखरखाव और संकट की स्थिति में संदेशों का आदान-प्रदान अब डिजिटल माध्यमों से भी संभव है। इससे भौगोलिक दूरी का सामाजिक अनुभव कुछ हद तक बदल सकता है। हालांकि डिजिटल संचार प्रत्यक्ष आमने-सामने की अंतःक्रिया को पूरी तरह समाप्त नहीं करता; दोनों प्रकार की अंतःक्रियाएँ एक-दूसरे के पूरक रूप में कार्य कर सकती हैं।

समुदाय के स्तर पर डिजिटल समूह स्थानीय समस्याओं की सूचना साझा करने, कार्यक्रमों के समन्वय और सामूहिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने में उपयोगी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी स्थानीय समस्या, सार्वजनिक सेवा या सामुदायिक आयोजन की सूचना तेजी से प्रसारित की जा सकती है। इससे सामुदायिक सहभागिता के नए अवसर बनते हैं। दूसरी ओर, यदि किसी समुदाय में अप्रमाणित सूचना तेजी से प्रसारित हो, तो वही नेटवर्क सामाजिक तनाव और अविश्वास का कारण भी बन सकता है। इसलिए डिजिटल सामुदायिक सहभागिता के साथ सूचना सत्यापन की क्षमता आवश्यक है। सामाजिक परिवर्तन का एक अन्य आयाम ग्रामीण युवाओं की आकांक्षाओं से जुड़ा है। डिजिटल मंचों के माध्यम से युवाओं को शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता और अन्य क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त होती है। इससे उनके संदर्भ-बिंदु स्थानीय समुदाय से आगे विस्तृत हो सकते हैं। लेकिन आकांक्षाओं का विस्तार तभी अवसर में बदलता है जब शिक्षा, कौशल, आर्थिक संसाधन और वास्तविक संस्थागत अवसर उपलब्ध हों। इस प्रकार सोशल मीडिया आकांक्षाओं को प्रभावित कर सकता है, पर वह स्वयं रोजगार या आर्थिक गतिशीलता की गारंटी नहीं देता।

### **भाषा, संस्कृति और स्थानीय ज्ञान**

ग्रामीण डिजिटल सहभागिता में भाषा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि डिजिटल सामग्री मुख्यतः ऐसी भाषा में उपलब्ध हो जिसे ग्रामीण उपयोगकर्ता आसानी से नहीं समझता, तो इंटरनेट की तकनीकी उपलब्धता के बावजूद उसका सामाजिक लाभ सीमित रह सकता है। स्थानीय भाषाओं और बोलियों में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी योजनाओं और आजीविका संबंधी सामग्री उपलब्ध होने से डिजिटल माध्यम अधिक सुलभ हो सकते हैं।

सोशल मीडिया स्थानीय सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के लिए भी मंच उपलब्ध करा सकता है। लोकगीत, स्थानीय कला, पारंपरिक ज्ञान, उत्सव और सामुदायिक अनुभव डिजिटल माध्यम से व्यापक दर्शकों तक पहुँच सकते हैं। इससे सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और पहचान को सार्वजनिक दृश्यता मिल सकती है। दूसरी ओर, डिजिटल सामग्री के तेज प्रसार में संदर्भ से बाहर की सामग्री या सांस्कृतिक सरलीकरण भी हो सकता है। इसलिए ग्रामीण डिजिटल संस्कृति के अध्ययन में स्थानीय समुदायों की अपनी व्याख्याओं और अनुभवों को महत्व देना आवश्यक है। स्थानीय ज्ञान और विशेषज्ञ ज्ञान के बीच संबंध भी महत्वपूर्ण है। किसान अपने अनुभवों को डिजिटल समूहों में साझा कर सकते हैं, लेकिन हर अनुभव वैज्ञानिक या स्थानीय परिस्थितियों के लिए समान रूप से उपयुक्त हो, यह आवश्यक नहीं है। अतः सोशल मीडिया को स्थानीय ज्ञान के

आदान-प्रदान का माध्यम मानते हुए सूचना की सत्यता और संदर्भ-संगति की जाँच को भी आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार करना चाहिए।

### निष्कर्ष

सोशल मीडिया ग्रामीण समाज में संचार, सामाजिक नेटवर्क, शिक्षा, कृषि, उद्यमिता और नागरिक सहभागिता के नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। इसके बावजूद डिजिटल परिवर्तन समान रूप से वितरित नहीं है। उपकरण की उपलब्धता, नेटवर्क, डेटा की वहनीयता, डिजिटल कौशल, शिक्षा, आय, लिंग और सामाजिक स्वायत्तता इसके उपयोग और परिणामों को प्रभावित करते हैं। इसलिए ग्रामीण समाज पर सोशल मीडिया के प्रभाव को केवल उपयोगकर्ताओं की संख्या या इंटरनेट पहुँच से समझना पर्याप्त नहीं है।

समाजशास्त्रीय दृष्टि से सोशल मीडिया ग्रामीण सामाजिक संरचना के साथ अंतःक्रिया करने वाली व्यवस्था है। यह पारंपरिक संबंधों का पूर्ण विकल्प नहीं है, बल्कि परिवार, समुदाय, जाति, स्वयं सहायता समूह, बाजार, विद्यालय और स्थानीय शासन के साथ जुड़कर सामाजिक जीवन को नया डिजिटल आयाम देता है। इसके लाभ तभी व्यापक हो सकते हैं जब डिजिटल पहुँच के साथ कौशल, स्वतंत्र उपयोग, विश्वसनीय सूचना और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध हो।

अतः ग्रामीण डिजिटल समावेशन को पहुँच, क्षमता और परिणाम के संयुक्त ढाँचे में विकसित करना आवश्यक है। विश्वसनीय इंटरनेट संपर्क, स्थानीय भाषा में डिजिटल एवं मीडिया साक्षरता, महिलाओं और कमजोर समूहों की स्वतंत्र डिजिटल पहुँच, उत्पादक आजीविका संबंधी उपयोग तथा साइबर सुरक्षा को एकीकृत रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस दिशा में भविष्य के प्राथमिक अनुभवजन्य अध्ययन ग्रामीण समाज में सोशल मीडिया के वास्तविक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों को अधिक सटीक रूप से मापने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

### संदर्भ

1. Laskar, M. H. H. (2023). Examining the emergence of digital society and the digital divide in India: A comparative evaluation between urban and rural areas. *Frontiers in Sociology*, 8. DOI: 10.3389/fsoc.2023.1145221.
2. Pandey, S. (2026). Beyond the Digital Divide: Social Media and Youth Social Behaviour in a Rural Community of Northern India. SSRN.
3. Pradhiba, S. P. M. (2026). Unequal Access in the Digital Era: A Multi-Dimensional Analysis of Digital Divide in Rural South India. *Journal of Daoist Studies*.
4. Rampal. (2019). A Research on the Effect of Social Media in the Development of Rural Society: A Review. *Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education*, 16(4), 1066–1071.
5. Press Information Bureau, Government of India. (2024, December 21). BharatNet: Bridging the Digital Divide.
6. Press Information Bureau, Government of India. (2024, December 19). Tele-Density and Wi-Fi Speed in the Country.
7. Digital literacy training and internet outcomes in rural marginalised communities in India. (2024). *International Journal of Lifelong Education*, 43(5).
8. Internet and Mobile Association of India (IAMAI) & Kantar. (2025). *स Internet in India 2024*.
9. Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India. National Sample Survey: Key Indicators of Household Social Consumption on Education in India.

10. Press Information Bureau, Government of India. (2026, January 29). Internet Connectivity in Rural and Remote Areas.
11. Press Information Bureau, Government of India. (2026, April 1). Internet Connections in Panchayats.
12. Singh, Y. (2000). Culture change in India: Identity and globalization. Rawat Publications.
13. Desai, A. R. (2010). Rural sociology in India. Popular Prakashan.